सिवनी

शब्दबाणों का प्रहार

राष्ट्रबाण

मध्य भारत का सबसे लो कप्रिय अखबार

संपादक : संजय बघेल

रविवार 15 मार्च 2026 E-PAPER: www.rashtrabaan.in • वर्ष : 10 • अंक : 315 • पृष्ठ : 06 • मूल्य : 5.00 रुपए www.facebook.com/rashtrabaan www.twitter.com/rashtrabaan

न्यूज ब्रीफ

शादी टूटने के बाद एचआईवी पॉजिटिव युवक ने खून इंजेक्ट किया

हैदराबाद। हैदराबाद में एक 24 साल के युवक ने कथित तौर पर एक 22 साल की महिला को एचआईवी-संक्रमित खून इंजेक्ट कर दिया। यह घटना तब हुई जब युवक के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने के बाद महिला के माता-पिता ने उसकी शादी युवक से तोड़ दी। यह घटना 11 मार्च की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और महिला रिश्तेदार हैं और महिला के माता-पिता ने शुरू में अपनी बेटी की शादी उसी से करने की योजना बनाई थी। चूंकि युवक के माता-पिता पहले से ही एचआईवी से संक्रमित थे, इसलिए महिला के माता-पिता ने पिछले साल सितंबर में युवक का एचआईवी टेस्ट करवाया।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ 'संसद घेराव' करेगी

नईदिल्ली। इंडियन यूथ कांग्रेस ने शनिवार को 16 मार्च को 'संसद घेराव' विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। संगठन का आरोप है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अमेरिका के साथ घोषित व्यापार समझौता भारत को नुकसान पहुंचाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकरा ने कहा कि पार्टी की युवा शाखा के कार्यकर्ता पूरे देश से जंतर-मंतर पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के साथ इकट्ठा होंगे।

हिंसा प्रभावित पश्चिम गारो हिल्स में कर्फ्यू बढ़ाया गया

शिलांग। मेघालय के हिंसा प्रभावित पश्चिम गारो हिल्स जिले में कर्फ्यू रविवार सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट विभोर अग्रवाल द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, यह पूरे जिले में लागू रहेगा, जिसमें शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक जरूरी चीजें खरीदने के लिए ढील दी जाएगी। इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि पूर्वी गारो हिल्स जिले में लगाया गया कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा। एक अन्य आदेश में जिला मजिस्ट्रेट आर पी मारक ने कहा कि पूर्वी गारो हिल्स में विलियमनगर मुख्य बाजार को सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

राष्ट्रबाण

अगर आपको नहीं मिल रहा है आपका लोकप्रिय अखबार राष्ट्रबाण तो आज ही अपने हॉकर से बोलिए या हमे कॉल कीजिए

सिर्फ 100 रुपए महीना

संपर्क : 7000427433

एलपीजी ला रहे 2 भारतीय जहाजों ने होर्मुज पार किया

ईरान ने कल गुजरने की इजाजत दी थी, 2-3 दिन में भारत पहुंचेंगे

राष्ट्रबाण | तेल अवीव | एजेंसी
rashtrabaan.in

अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज 15वां दिन है। खाड़ी देशों से एलपीजी लेकर आ रहे भारत के दो जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार कर गए हैं। ईरान ने एक दिन पहले इन जहाजों को गुजरने की अनुमति दी थी और अब ये भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहे हैं।

शिपिंग जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा के मुताबिक भारतीय झंडे वाले एलपीजी कैरियर शिवालिक और नंदा देवी ने शनिवार होर्मुज स्ट्रेट पार किया। दोनों जहाज कुल 92,700 टन एलपीजी लेकर भारत आ रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि दोनों जहाज गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाह की ओर जा रहे हैं और इनके अगले 2-3 दिनों में भारत पहुंचने की संभावना है। ये दोनों जहाज उन 24 जहाजों में शामिल थे, जो मिडिल-ईस्ट में जंग शुरू होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से में फंस गए थे।

इससे पहले भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने शुक्रवार को कहा था कि ईरान ने कई भारतीय जहाजों को इस जलमार्ग से गुजरने की अनुमति दी है, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कुल कितने जहाजों को अनुमति दी गई।

इजराइली रक्षा मंत्री बोले- ईरान के साथ युद्ध फाइनल स्टेज में: इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध अब फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। उन्होंने ईरान के खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी हमलों की तारीफ करते हुए कहा कि संघर्ष निर्णायक मोड़ पर है।

काट्ज ने सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ वैश्विक और क्षेत्रीय संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है।

यूएई ने ईरान की 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन मार गिराए

संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शनिवार को ईरान से दागे गए 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया।

यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि शनिवार सुबह से ईरान की ओर से किए गए हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक रोक दिया और सभी मिसाइल व ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। मंत्रालय के अनुसार 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद अब तक यूएई की एयर डिफेंस ने 294 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1,600 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है।

ईरानी युद्धपोत आईआरआईएस लावन अब भी कोच्चि में खड़ा

ईरानी नौसेना का जहाज आईआरआईएस लावन अभी भी केरल के कोच्चि बंदरगाह पर खड़ा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जहाज के गैर-जरूरी क्रू सदस्य और भारत में फंसे अन्य ईरानी नागरिक चार्टर्ड फ्लाइट से अपने देश लौट गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि आईआरआईएस लावन को तकनीकी खराबी के कारण कोच्चि में डॉक किया गया था। ईरान ने 28 फरवरी को जहाज के लिए आपात डॉकिंग की अनुमति मांगी थी और भारत ने 1 मार्च को इसकी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि मिडिल-ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण कई ईरानी नागरिक भारत में फंस गए थे। ईरानी अधिकारियों ने चार्टर्ड फ्लाइट का इंतजाम कर इन नागरिकों और जहाज के गैर-जरूरी क्रू को वापस भेजा। आईआरआईएस लावन फरवरी में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 और मिलान 2026 में हिस्सा लेने के लिए भारत आया था और तकनीकी समस्या के कारण अब भी कोच्चि पोर्ट पर खड़ा है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि मिडिल-ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच भारत लगातार तनाव कम करने और संवाद का समर्थन कर रहा है।

अमेरिका बोला- खार्ग आइलैंड पर 90 ईरानी सैन्य ठिकाने नष्ट

अमेरिका ने दावा किया है कि उसकी सेना ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर बड़े पैमाने पर सटीक हमले किए, जिनमें 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार हमले में तेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। CENTCOM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि हमले में नौसैनिक माइंस के भंडारण केंद्र, मिसाइल स्टोरेज बंकर और कई अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेना ने इसे 'लार्ज-स्केल प्रिसिजन स्ट्राइक' बताया। इससे पहले एक ईरानी अधिकारी ने कहा था कि खार्ग आइलैंड से तेल निर्यात बिना किसी रुकावट के जारी है और वहां तेल कंपनियों की गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं।

कोलकाता- मोदी की रैली से पहले भाजपा-टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प

ममता की मंत्री बोलीं- मुझे ईंट मारी गई; पीएम बोले- जंगलराज वालों का काउंटडाउन शुरू

राष्ट्रबाण | कोलकाता | एजेंसी
rashtrabaan.in

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पीएम मोदी की रैली से पहले भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ है। गिरीश पार्क एरिया में दोनों ग्रुप ने एक-दूसरे पर पत्थरबाजी की। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। पश्चिम बंगाल में उद्योग, वाणिज्य और उद्यम मंत्री शशि पंजा ने आरोप लगाया कि झड़प के दौरान मुझ पर ईंट मारी गई। भाजपा गुंडा नहीं है, हत्यारी है। मंत्री पंजा का यहीं पर घर है।

कोलकाता में अपने संबोधन कि दौरान पीएम ने कहा कि जंगलराज वालों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये निर्मम वाली सरकार का अंत करीब आ गया है। पीएम ने कहा कि पहले कांग्रेस, फिर कम्यूनिस्ट अब टीएमसी, ये लोग एक के बाद एक आते रहे और अपनी जेब भरते रहे। मोदी ने कहा कि अब समय आ गया है ये हालात बदले, बंगाल के युवाओं को बंगाल में काम मिले, नौजवान बंगाल के विकास का नेतृत्व करे।

दरअसल, पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 18,680 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन-शिलान्यास किया। उनके साथ मंच पर बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल के गवर्नर आरएन रवि मौजूद रहे।

पीएम की स्पीच की पांच बड़ी बातें...

- भाजपा बंगाल को महान बनाने के लिए काम करेगी। सही नीतियों और नीयत से राज्य में विकास होगा और किसानों, युवाओं, व्यापारियों और छात्रों को फायदा मिलेगा।
- राज्य की मौजूदा सरकार केंद्र की योजनाओं को लोगों तक नहीं पहुंचने देती और कटमनी के कारण गरीबों को उनका हक नहीं मिल पाता।
- बंगाल में युवाओं को न अच्छी शिक्षा मिल रही है और न रोजगार। किसान भी परेशान हैं और कई लोगों को काम के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है।
- राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाओं के खिलाफ घटनाएं चिंता का विषय हैं। भाजपा सरकार आने पर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
- पहले कांग्रेस, फिर वामपंथ और अब टीएमसी ने राज्य पर शासन किया, लेकिन अब बदलाव का समय आ गया है। भाजपा सरकार बनने पर सबका साथ, सबका विकास होगा और सबका हिसाब किया जाएगा।

अडाणी पावर प्लांट में आगजनी, गाड़ियों में तोड़फोड़ : सिंगरौली में लेबर की मौत पर भड़के

कर्मचारी को पीटा, काम छोड़ लौटे कई मजदूर

राष्ट्रबाण | सिंगरौली | एजेंसी
rashtrabaan.in

सिंगरौली जिले के माडा थाना क्षेत्र के बधौरा स्थित अडाणी पावर प्लांट में शनिवार सुबह मजदूर की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। गुस्साए मजदूरों ने प्लांट परिसर में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। सामने आए वीडियो में दूर से काले धुएं का बड़ा गुबार नजर आ रहा है। प्लांट के अंदर एक साइट के नीचे भी आग लगी हुई है।

हालात को काबू में करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, प्लांट में काम करने वाले मजदूर लल्लन सिंह की शुक्रवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी। मृतक मूल रूप से झारखंड के गढ़वा जिले का रहने वाला था और लंबे समय से इसी प्लांट में काम कर रहा था।

मजदूर की मौत की खबर फैलते ही साथी मजदूरों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने शव छिपाने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि ये अफवाह भी फैली कि मजदूर लल्लन की ऊंचाई से गिरने के कारण मौत हुई है। कंपनी प्रबंधन और जिला प्रशासन का दावा है कि मजदूर की मौत देर रात हार्ट अटैक से हुई।

राहुल बोले- डीयू में जाति देखकर इंटरव्यू में फेल करते हैं : यूनिवर्सिटी ने कहा- बयान से पहले फैक्ट चेक करें

राष्ट्रबाण | नईदिल्ली | एजेंसी
rashtrabaan.in

कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को कांशीराम जयंती पर हुए संविधान सम्मेलन में हिस्सा लेने लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) में जाति देखकर इंटरव्यू में फेल करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा- 'मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था। इंटरव्यू में बच्चों को निकालने का तरीका है। आपकी जाति क्या है भैया, आप इंटरव्यू में फेल।'

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राहुल के इस बयान को खारिज कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने X पर एक पोस्ट में लिखा- यूनिवर्सिटी ष्टश्वञ्ज स्कोर के आधार पर एडमिशन देती है। कई ग्रेजुएशन-पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस के लिए इंटरव्यू जरूरी नहीं हैं। राहुल को बयान देने से पहले फैक्ट्स की जांच करना चाहिए।

राहुल बोले- मोदी साइकोलॉजिकली खत्म, वे अब प्रधानमंत्री नहीं: राहुल ने शनिवार को कहा था, नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली खत्म हो गए हैं। मोदी अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे, वे अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं और नरेंदर ने सरेंडर कर दिया है। जब मैं यह बात संसद में बोलने जा रहा था तो नरेंद्र मोदी जी भाग कर निकल गए। उन्होंने कहा- नरेंद्र मोदी ने देश की एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता कर लिया है। क्योंकि अब अमेरिका तय कर रहा है कि हम तेल कहां से लेंगे? एनर्जी सेक्टर के हालात अभी और खराब होंगे। राहुल ने कहा कि कांशीरामजी समाज में बराबरी की बात करते थे। अगर जवाहर लाल नेहरू जी जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते।

डीयू बोली- ऐसे कमेंट्स से यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करते हैं

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यदि राहुल गांधी का संकेत फैकल्टी रिक्रूटमेंट पर था, तो हाल के समय में सभी कैटेगरी में हजारों शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं। डीयू ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा- हम ऐसी टिप्पणियों का कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि वे विश्वविद्यालय में एक ऐसा माहौल बनाती हैं जो पढ़ाई-लिखाई के लिए अनुकूल नहीं होता।

सरकार ने सोनम वांगचुक पर लगा एनएसए हटाया : 170 दिन बाद जोधपुर जेल से रिहा

लेह हिंसा के बाद हिरासत में लिए गए थे

राष्ट्रबाण | नईदिल्ली | एजेंसी
rashtrabaan.in

केंद्र ने शनिवार को लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक पर लगा नेशनल सिक्युरिटी एक्ट (एनएसए) हटा दिया। सरकार ने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। गृह मंत्रालय के अनुसार, सोनम ने एनएसए एक्ट के तहत अपनी हिरासत की अवधि का लगभग आधा हिस्सा पूरा कर लिया है।

इसके बाद सुबह करीब 10 बजे सोनम की पत्नी गीतांजलि जोधपुर जेल पहुंचीं। इसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी की गई। फिर दोपहर सवा एक बजे पत्नी के साथ एक निजी गाड़ी से जेल से निकले।

दरअसल, सोनम के अनशन के दौरान 24 सितंबर 2025 को लेह हिंसा हुई थी। दो दिन बाद 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत वांगचुक को हिरासत में लिया था। इसके बाद उन्हें फौरन जोधपुर शिफ्ट कर दिया था। 170 दिन से वे जोधपुर जेल में हैं। अब उनकी रिहाई होगी। एनएसए सरकार को ऐसे लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है, जिनसे देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो। इसके तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने तक नजरबंद रखा जा सकता है। सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में वांगचुक की याचिका पर अंतिम सुनवाई (17 मार्च) के दो दिन पहले लिया। कोर्ट सुनवाई के दौरान वे वीडियो और फोटो देखेगा, जिनके आधार पर सरकार ने उन पर एनएसए लगाया था।

सरकार बोली- घबराकर बुकिंग न करें ; दिल्ली के होटल-रेस्टोरेंट कचरे से बनी गैस इस्तेमाल करें

5 दिन बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर से रोक हटी

राष्ट्रबाण | नईदिल्ली | एजेंसी
rashtrabaan.in

सरकार ने 5 दिन बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर लगी रोक हटा दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कमर्शियल सिलेंडर का वितरण शुरू कर दिया गया है। सरकार ने 9 मार्च को कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगाई थी।

वहीं, सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को रोकने के लिए देशभर में छापेमारी तेज कर दी गई है। सरकार ने कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है।

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने कहा कि अब दिल्ली-एनसीआर की इंडस्ट्रीज, होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी संस्थाओं को एक महीने के लिए नेचुरल गैस की जगह बायोमास से बने पेलेट्स, खासकर रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल (आरडीएफ) पेलेट्स के अस्थायी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है।

सरकार बोली-दिल्ली के होटल-रेस्टोरेंट कचरे से बनी गैस इस्तेमाल करें

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने कहा कि अब दिल्ली-एनसीआर की इंडस्ट्रीज, होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी संस्थाओं को एक महीने के लिए नेचुरल गैस की जगह बायोमास से बने पेलेट्स, खासकर रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल पेलेट्स के अस्थायी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी सीएक्यूएम ने यह आदेश जारी किया है। रिफ्यूज-डिराइव्ड फ्यूल असल में कचरे से बनाया गया एक तरह का ईंधन है। इसमें नगर निगम और इंडस्ट्रीज से निकलने वाले सूखे कचरे- जैसे प्लास्टिक, कागज, कपड़ा और लकड़ी को प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले कचरे को छांटकर उसमें से ऐसी चीजें निकाली जाती हैं जो जल नहीं सकतीं (जैसे कांच या धातु) और फिर बाकी बचे हिस्से को मशीन से छोटे-छोटे टुकड़ों या पेलेट्स (गोलियों) में बदल दिया जाता है।

राष्ट्रबाण
सिवनी, रविवार 15 मार्च 2026

बैतूल राष्ट्रबाण

● मुलताई ● बैतूल बाजार ● आमला ● भैंसादंड ● सारणी ● बोरदई ● आठनेर

मप्र राज्य कर्मचारी संघ ने टीईटी आदेश को बताया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत

25 वर्षों से कार्यरत शिक्षकों पर टीईटी थोपने का विरोध, तीन लाख कर्मचारियों में आक्रोश

बैतूल| संवाददाता
rashtrabaan.in

टीईटी परीक्षा को लेकर जारी आदेश के विरोध में मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने कड़ा रुख अपनाते हुए कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, विधि विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को ज्ञापन भेजकर आदेश वापस लेने की मांग की है। संघ ने आरोप लगाया है कि आदेश जारी करते समय शासन की प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जिससे प्रदेश के लगभग तीन लाख शिक्षा विभाग के कर्मचारियों में भय और रोष का वातावरण बन गया है। ज्ञापन में मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सचिन राय ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक यूसीआर/सी/85/प्रा.मा.शि./2025 -26 दिनांक 3 मार्च 2023/26 में टीईटी परीक्षा के संबंध में आदेश जारी किया गया है, लेकिन इसकी भाषा और उल्लेख से स्पष्ट होता है कि इस विषय में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल, सचिवालय स्तर या स्कूल शिक्षा सचिवालय से कोई सलाह, अभिमत या लिखित अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि शासन नीति के अनुसार ऐसे निर्णयों में राज्य स्तर पर अनुमोदन आवश्यक होता है, जो आदेश में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील क्रमांक 1385/2025 में याचिकाकर्ता एक अशासकीय शिक्षण संस्था है तथा उत्तरदाता राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद नई दिल्ली है। संघ ने सवाल उठाया कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा क्या मध्यप्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल को जुलाई माह में टीईटी परीक्षा कराने के लिए कोई स्पष्ट आदेश या निर्देश दिए गए हैं, इसका उल्लेख आदेश में नहीं है। संघ ने बताया कि मध्यप्रदेश के अध्यापक, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक अपनी पहली नियुक्ति शिक्षाकर्मी और संविदा शिक्षक के रूप में प्राप्त कर सेवा में निरंतर कार्यरत हैं। यह नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सिविल अपील क्रमांक 4032/1995 मध्य प्रदेश शासन अन्य विरुद्ध दिनेश कुमार अन्य, दिनांक 21 अक्टूबर 1997 तथा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी शिक्षाकर्मी भर्ती अधिनियम 1997 के आधार पर की गई थीं। इसके बाद शिक्षाकर्मी भर्ती अधिनियम 1998, अध्यापक भर्ती अधिनियम 2008 और राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियम 2018 लागू किए गए, जिनमें कहीं भी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना सेवा शर्त के रूप में उल्लेखित नहीं है।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील क्रमांक 2634/2013 में स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति के बाद उसकी भर्ती से संबंधित सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसे में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश शासन की कार्यालयीन प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत प्रतीत होता है। संघ ने मांग की है कि इस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, अन्यथा प्रदेश के शिक्षा विभाग में व्यापक असंतोष की स्थिति बनेगी।

ज्ञापन के दौरान सचिन राय जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ, संजय ठाकुर संभागीय अध्यक्ष, एन के गलफट, पंजाब गायकवाड़, भीम धोटे, रवि सरनेकर, आशिषचंद्र शर्मा, राजेंद्र कटारे, प्रविण नरवरे, नितेश राठौड़, अनिल कापसे, शैलेन्द्र बिहारीया, राजेंद्र प्रसाद साहु, राजकुमार राठौड़, मुकेश सरियाम, हरिराम, नरेंद्र वागद्रे, प्रदीप राने, साहेबराव चिल्हाटे, नारायण सिंह नगदे, चंचल पांसे, मंगलमुर्ती पाटनकर, दुर्गेश मालवीय, आर आर धोटे, श्रीमती प्रेमवती उईके, अमीना खान, भगोती परते, दरशन वामनकर, शिरिस वर्मा, श्यामदेव ब्रहामणे, ओम प्रकाश सरोने, प्रदीप कुमार राने, संतोष राठौर, राजकुमार राठौड़, वीरेंद्र धुर्वे, विशन आहाके, हेमंत जैन, सुभाष बागवे, प्रवीण कुमार शर्मा, नितेश राठौर, एस ठाकरे, आर रघुवंशी, आर आर धोटे, आर के मालवीय, सुनील पंडाग्रे सहित सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे।

जंगल बचाने उतरे लोक कलाकार

आदिवासी बोली के नुक्कड़ नाटक से ग्रामीणों को वनाग्नि से बचाव का दिया संदेश

बैतूल| संवाददाता
rashtrabaan.in

गर्मी के मौसम में जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग ने इस बार जनजागरूकता का अनोखा तरीका अपनाया है। आदिवासी अंचलों में स्थानीय बोली में नुक्कड़ नाटक कर ग्रामीणों को वनाग्नि से होने वाले नुकसान और उससे बचाव का संदेश दिया जा रहा है। वन संरक्षक बैतूल मधु व्ही. राज, दक्षिण वनमंडल के डीएफओ अरिहंत कोचर, एसडीओ पांडे और आमला रेंज के रेंजर नानकराम कुशवाह की पहल पर यह अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत आमला रेंज के वनग्राम लादी में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर ग्रामीणों को जंगलों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में एकलव्य लोक कला समिति बैतूल के लोक कलाकार बसंत कवड़े और उनकी टीम ने स्थानीय आदिवासी बोली में नाटक प्रस्तुत कर सैकड़ों ग्रामीणों को जंगल और वन्य प्राणियों की सुरक्षा का संदेश दिया। कलाकारों ने नाटक के माध्यम से बताया कि महुआ बीनने और तेंदूपत्ता संग्रहण के दौरान कई बार अनजाने में लगाई गई आग पूरे जंगल को भारी नुकसान पहुंचा देती है। इससे वन संपदा नष्ट होती है और वन्य जीवों का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। वन विभाग के अनुसार हर वर्ष गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसे रोकने के लिए विभाग सैटेलाइट डेटा से निगरानी, फायर लाइन निर्माण, वनकर्मियों की लगातार गश्त और जनजागरूकता अभियान जैसे उपाय कर रहा है। दक्षिण वनमंडल द्वारा इस बार ग्रामीण अंचलों में स्थानीय कलाकारों की मदद से नुक्कड़ नाटक आयोजित कर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

जंगलों की सुरक्षा का लिया संकल्प

नाटक के दौरान ग्रामीणों को जंगलों की सुरक्षा का संकल्प भी दिलाया गया और आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील की गई। वन अधिकारियों का कहना है कि फायर सीजन के दौरान महुआ और तेंदूपत्ता संग्रहण के समय आग लगने का खतरा सबसे अधिक रहता है, ऐसे में ग्रामीणों की जागरूकता से आगजनी की घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। कार्यक्रम में परिक्षेत्र अधिकारी आमला नानकराम कुशवाह, परिक्षेत्र सहायक लादी राजेंद्र मोखलगाय, परिक्षेत्र सहायक आमला योगेश साहू, बीट गार्ड मंगारा विशाल वामने, बीट गार्ड लादी भीमराव सातनकर, बीट गार्ड बीजादेही यशवंत सिंह चौहान, बीट गार्ड खतेड़ा देवेंद्र सिंह ठाकुर, बीट गार्ड कलमेश्वरा अरुण प्रताप कौरव, बीट गार्ड पचामा बिजेंद्र कैथवास तथा सरपंच राजू शिलुकर सहित ग्रामीण रूटूं, बबलू और बड़ी संख्या में गांव के लोग उपस्थित रहे।

किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ऋण वसूली की तारीख 30 अप्रैल तक बढ़े : निलय डागा

बैतूल| संवाददाता
rashtrabaan.in

जिले में इन दिनों किसानों के बीच एक अजीब विरोधाभास खड़ा हो गया है। एक तरफ खेतों में गेहूं की फसल कटने की तैयारी में खड़ी है, दूसरी ओर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बैतूल द्वारा ऋण वसूली के लिए मुनादी की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि अभी तक पूरे जिले में गेहूं खरीदी की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन किसानों को बताया जा रहा है कि यदि उन्होंने 15 मार्च तक ऋण की राशि जमा नहीं की तो उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निलय डागा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह स्थिति किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि जब खेतों में खड़ी फसल की कटाई अभी शुरू ही हुई है और जिले में गेहूं खरीदी का काम भी शुरू नहीं हुआ है, तब किसानों से 15 मार्च तक ऋण जमा करने का दबाव बनाना पूरी तरह से अव्यवहारिक और किसान विरोधी कदम है। श्री डागा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार और उसकी व्यवस्था किसानों की वास्तविक स्थिति को समझने के बजाय कागजी समय सीमा के पीछे भाग रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसान क पास अभी उपज का पैसा ही नहीं आया, तो वह ऋण कैसे चुकाएगा।

इधर कर्ज की मुनादी, उधर खेतों में खड़ी है फसल

कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि शहर में लाउडस्पीकर के माध्यम से ऋण वसूली के लिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जिला बैतूल के माध्यम से ऋणी किसानों को सार्वजनिक रूप से यह सूचना दी जा रही है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना ऋण जमा करें, तभी उन्हें शासन से मिलने वाली योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। साथ ही यह भी चेतावनी दी जा रही है कि यदि समय पर ऋण वसूली जमा नहीं की गई तो भविष्य में कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। किसानों से यह भी कहा जा रहा है कि तत्काल वसूली जमा कर खाद-बीज ऋण की राशि प्राप्त करें।

30 अप्रैल तक बढ़ाई जाए ऋण वसूली की अंतिम तिथि

निलय डागा ने मांग करते हुए कहा कि ऋण वसूली की अंतिम तिथि कम से कम 30 अप्रैल तक बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने और आर्थिक रूप से व्यवस्थित होने का समय मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि सरकार किसानों का सम्मान करती है तो उसकी जमीनी हालात को देखते हुए तत्काल निर्णय लेना चाहिए।

गांव-गांव से खोजकर सम्मानित की गईं संघर्षशील महिलाएं

संघर्ष से जीवन गढ़ने वाली महिलाओं को साड़ी, शॉल और श्रीफल देकर किया सम्मानित

बैतूल| संवाददाता
rashtrabaan.in

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी महिला संगठन ने समाज में संघर्ष कर अपने परिवार का पालन-पोषण करने वाली महिलाओं का सम्मान कर एक अलग पहल प्रस्तुत की। संगठन की टीम ने ऐसी महिलाओं को खोजकर सामने लाने का प्रयास किया, जिन्होंने जीवन की कठिन परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानी और अपने परिवार को संभालते हुए समाज के लिए प्रेरणा का उदाहरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान संगठन की प्रदेश अध्यक्ष कविता उमाकांत मालवी, प्रदेश महामंत्री सरिता पवार, जिला अध्यक्ष लता सोनी और सचिव पिंकी नामदेव की मौजूदगी में विभिन्न गांवों से चयनित महिलाओं का सम्मान किया गया। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि मंचों पर अक्सर कई लोगों का सम्मान किया जाता है, लेकिन संगठन ने इस बार उन महिलाओं को चुनने का निर्णय लिया जो वास्तव में सम्मान की हकदार हैं और जिनके संघर्ष से समाज को सीख मिलती है कि महिलाएं कभी हार नहीं मानतीं। कार्यक्रम में चयनित महिलाओं का फूलमाला पहनाकर, तिलक लगाकर, श्रीफल, शॉल और साड़ियां भेंट कर सम्मान किया गया। संगठन की टीम ने गांवों में जाकर ऐसी महिलाओं की पहचान की जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए आत्मसम्मान और संघर्ष की मिसाल बन रही हैं। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी महिला संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में उन महिलाओं को सामने लाना है जो चुपचाप संघर्ष करते हुए परिवार और समाज को संभाल रही हैं और जिनकी कहानी अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन सकती है।

धार्मिक व मांगलिक कार्यक्रमों में घटा शराबखोरी का उपद्रव

सर्व समाज की पहल से दिखने लगा असर, गोंड, गवली, कोरकू, कुनबी, मेहरा समाज एक मंच पर

बैतूल| संवाददाता
rashtrabaan.in

जिले के सामाजिक इतिहास में पहली बार गोंड समाज, गवली समाज, कोरकू समाज, कुनबी समाज, मेहरा समाज सहित विभिन्न समाजों के सामाजिक नेतृत्वकर्ता शराबबंदी के मुद्दे पर एक मंच पर एकजुट हुए हैं। सर्व समाज संयुक्त मोर्चा द्वारा शुरू किए गए इस सामूहिक अभियान के सकारात्मक परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं और जिले में चल रहे धार्मिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों में पहले की तुलना में शराब पीकर उत्पात मचाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी देखी जा रही है। समाज में बढ़ती शराबखोरी से उत्पन्न अपराध, सड़क दुर्घटनाओं, पारिवारिक कलह और युवाओं के भविष्य पर पड़ रहे दुष्प्रभावों को देखते हुए सर्व समाज संयुक्त मोर्चा द्वारा यह पहल शुरू की गई थी। अब इसके प्रभाव से सामाजिक आयोजनों में अनुशासन और शांति का माहौल बनता नजर आ रहा है, जिसे समाज के वरिष्ठजन भी सकारात्मक बदलाव के रूप में देख रहे हैं। संयुक्त मोर्चा से जुड़े विभिन्न समाज संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने, सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा प्रभावी शराबबंदी लागू करने की मांग की है। समाज के वरिष्ठजनों और नेतृत्वकर्ताओं का कहना है कि शराब केवल एक व्यक्ति को ही नहीं पूरे परिवार और समाज को विनाश की ओर ले जाती है। उनका कहना है कि यदि समय रहते इस बुराई पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका गंभीर दुष्प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। समाज प्रमुखों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान किसी एक समाज या वर्ग का नहीं बल्कि सर्व समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि शराब के दुष्प्रभावों को समझते हुए इस सामाजिक बुराई के खिलाफ प्रशासन और समाज संगठनों का सहयोग करें। सर्व समाज संयुक्त मोर्चा की यह पहल सामाजिक सुधार, शांति और सुरक्षित समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है।

ताप्ती रेंज में वनरक्षक पर अवैध वसूली और सागौन तस्करी के आरोप

बैतूल। ताप्ती रेंज के महुपानी सर्किल की महुपानी बीट में पदस्थ वनरक्षक पर भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और वन संसाधनों के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्राम बोरगांव निवासी मनोज धोटे ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2022 में जब लेखराज सिंह धाकड़ चिखली सर्किल की मकड़ा बीट और इटिया बिटिया बीट में पदस्थ थे, उस दौरान उनके फूफा मंचितराव महाले दो बैलों के साथ जंगल में मवेशी चराने गए थे। उसी समय क्षेत्र में किसी ग्रामीण द्वारा जलाऊ लकड़ी एकत्रित की गई थी। आरोप है कि मौके पर पहुंचे लेखराज सिंह ने बिना प्रमाण मंचितराव महाले पर लकड़ी काटने का आरोप लगाकर गाली-गलौज की और अवैध सागौन तथा वन्य प्राणी अधिनियम में केस बनाने की धमकी दी।

मजदूरों की एकता रंग लाई : बकाया वेतन भुगतान के आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित होने की संभावना

सारनी| संवाददाता
rashtrabaan.in

पाथाखेड़ा क्षेत्र की कोयला खदानों में कार्यरत ठेका मजदूरों के बकाया वेतन को लेकर जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन अब समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। शनिवार दोपहर लगभग 12 बजे श्रम अधिकारी आशीष गुप्ता आंदोलन स्थल पर पहुंचे और मजदूरों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इसके बाद प्रबंधन एवं ठेकेदारों के साथ चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में यह सहमति बनी कि प्रबंधन के नियमानुसार तीन दिनों के भीतर मजदूरों का बकाया वेतन उनके बैंक खातों में जमा कराया जाएगा। इस आश्वासन के बाद मजदूरों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। श्रम अधिकारी ने ठेकेदारों के साथ विशेष चर्चा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मजदूरों को उनका संपूर्ण वेतन समय पर प्रदान किया जाए तथा भविष्य में किसी भी मजदूर के वेतन में अनावश्यक देरी या बिना कारण कार्य से हटाने जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। इसके अतिरिक्त कई वर्षों से लंबित कुछ मजदूरों के सीएमपीएफ (कोल माइंस प्रोविडेंट फंड) की कटी हुई राशि को भी आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर वापस दिलाने की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान श्रमिकों के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से प्रदीप नागले, मनोज पवार, संतोष देशमुख, बाबूलाल भारती, धर्मेन्द्र चौरे, लिखीराम, बलराम देशमुख, मोहन, अजय सहित अन्य समाजसेवी एवं मजदूर प्रतिनिधि मौजूद रहे।

बैतूल में कोल माइंस सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बैठक में सरकार पर नाराजगी

कोल पेंशनरों को अब तक नहीं मिला वेतन समझौता और पेंशन वृद्धि का लाभ

बैतूल| संवाददाता
rashtrabaan.in

कोल माइन सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ एचएमएस की बैठक में कोल पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर नाराजगी खुलकर सामने आई। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2018 से 2023 तक के वेतन समझौता क्रमांक 11 के एरिया तथा पेंशन वृद्धि का भुगतान अब तक पेंशनरों को नहीं मिला है, जबकि भारत सरकार का राजपत्र जारी हुए लगभग दो से तीन वर्ष हो चुके हैं। बैठक में यह भी कहा गया कि जिन पेंशनरों को एक हजार रुपये से कम मासिक पेंशन मिल रही है, उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपये देने का प्रावधान भारत सरकार के राजपत्र में वर्ष 2023-24 में आदेशित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पाथाखेड़ा क्षेत्र के पेंशनरों को अब तक इसका लाभ नहीं दिया गया है। बैठक में लोक लेखा समिति की उस रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया जो 18 मार्च 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई थी। इसके साथ ही सीएमपीएफ 1998 पेंशन योजना में संशोधन कर पेंशन रिवीजन और पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर वर्ष 2019 से जंतर-मंतर नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन किए जाने की जानकारी दी गई। इस दौरान बनारस, धनबाद और कोलकाता में भी धरना प्रदर्शन कर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया, लेकिन देश के लगभग छह लाख कोल पेंशनरों की मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

जिले के पचास हजार पेंशनरों की मांगों पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं

बैठक में कहा गया कि बैतूल जिले के सांसद और केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उईके को भी कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन जिले के लगभग पचास हजार पेंशनरों की मांगों पर अब तक कोई ठोस पहल दिखाई नहीं दी। बैठक में 12 मार्च 2026 को कोल मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली में आयोजित पेंशनर स्थिरता समिति की बैठक का भी जिक्र किया गया। इसमें देश की प्रमुख यूनियन बीएमएस के मजदूर हितेषी यूनियन के सदस्य के एल रेड्डी के लगातार सात बैठकों में अनुपस्थित रहने पर भी नाराजगी व्यक्त की गई। बैठक में भारत सरकार से कोल पेंशनरों की पेंशन वृद्धि कर रिवीजन करने, दो हजार रुपये प्रतिमाह डोमेस्टिक मेडिकल अलाउंस पेंशनरों, स्टॉफ और कर्मचारियों को दिए जाने की मांग की गई।

बैठक में ये रहे मौजूद

बैठक में निर्णय लिया गया कि ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के संयोजक पी के सिंह राठौड़ के आह्वान पर 30 मार्च को जंतर-मंतर नई दिल्ली में आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन में जिला बैतूल से लगभग 40 से 50 सदस्य भाग लेंगे। बैठक में अध्यक्ष डीके साहू, महामंत्री डीआर झरबडे, उपाध्यक्ष अजय सिंह राजपूत, दिनेश कुमार शर्मा, दामोदर प्रसाद मिश्रा, शिवदयाल चौकीदार, माणिकराव, नागोराव वागद्रे, रामदास पंडाग्रे, विजयके शर्मा, कुंदन लाल चौधरी, शब्बीर खान, गुलाब राव, कृष्ण राव उबनारे, रामदास पंडाग्रे, तुलसीराम मासोदकर, अशोक, सुखराम पवार सहित एचएमएस के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

नि:शुल्क पंचकर्म शिविर में 360 लोगों ने लिया उपचार का लाभ

टिकारी आयुर्वेद चिकित्सालय और आयुष विंग में लगा नि:शुल्क पंचकर्म शिविर

बैतूल| संवाददाता
rashtrabaan.in

आयुष विभाग द्वारा आमजन के बेहतर स्वास्थ्य और आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित नि:शुल्क पंचकर्म चिकित्सा शिविर को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला। जिला आयुर्वेद चिकित्सालय टिकारी और जिला चिकित्सालय परिसर स्थित आयुष विंग में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे और उन्होंने परामर्श के साथ उपचार का लाभ लिया। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर योगेश चौकीकर के निर्देशन में आयोजित शिविर का संचालन अनुभवी डॉक्टरों और विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया गया। जिला आयुर्वेद चिकित्सालय टिकारी में नोडल अधिकारी डॉ. प्रियंका और सहायक नोडल अधिकारी डॉ. नरेंद्र डडोरे के मार्गदर्शन में मरीजों को उपचार दिया गया। वहीं जिला चिकित्सालय परिसर स्थित आयुष विंग में नोडल अधिकारी डॉ. प्रियंका उइके और सहायक नोडल अधिकारी डॉ. सरिता डहेरिया के मार्गदर्शन में विभाग के कर्मचारियों ने मरीजों को सेवाएं प्रदान कीं। शिविर के दौरान लोगों में पंचकर्म चिकित्सा के प्रति विशेष रुचि देखने को मिली। मरीजों ने सामान्य बीमारियों के लिए परामर्श लेने के साथ ही पंचकर्म जैसी प्राचीन और प्रभावशाली आयुर्वेदिक पद्धति के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रीना चौकीकर ने बताया कि पंचकर्म शरीर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जो कई पुरानी और जटिल बीमारियों में लाभकारी सिद्ध होती है। आयुष विभाग समय-समय पर ऐसे निःशुल्क शिविरों का आयोजन करता है, ताकि समाज के हर वर्ग तक आयुर्वेद और पंचकर्म का लाभ पहुंचाया जा सके। शिविर में आए लोगों ने विभाग की इस पहल की सराहना की और बताया कि इस तरह के आयोजनों से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उपचार की सुविधा मिलती है।

फॉलोअप: ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर फैलता जाल, युवाओं के खातों से हो रहे संदिग्ध लेन-देन

बिचौलियों के जरिए खुलवाए जा रहे बैंक खाते, कई नामों की चर्चा जांच की उठी मांग

राष्ट्रबाण शहडोल| संवाददाता rashtrabaan.in

शहर में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़े एक कथित नेटवर्क को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में सक्रिय बताए जा रहे इस गिरोह पर आरोप है कि आर्थिक रूप से कमजोर और बेरोजगार युवाओं को लालच देकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाए जा रहे हैं। बाद में इन खातों के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए जाने की बात सामने आ रही है। जानकरों की माने तो इस पूरे मामले में कुछ युवक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। वे जरूरतमंद लोगों को कुछ पैसे देने का प्रलोभन देकर उनके दस्तावेजों से बैंक खाते खुलवाते हैं और फिर इन खातों का उपयोग ऑनलाइन गेमिंग व सट्टेबाजी से जुड़े लेन-देन के लिए किया जाता है। चर्चा है कि इस प्रक्रिया में कमीशन का खेल भी चल रहा है और नेटवर्क कई स्तरों पर काम कर रहा है।

अलग-अलग क्षेत्रों से चर्चा में कुछ नाम

सूत्रों की माने तो शहर के सौखी मोहल्ला, सिंधी बाजार, सिंहपुर, स्टेडियम रोड, बस स्टैंड, मोहनराम तालाब और बगिया तिराहा क्षेत्र में रहने वाले कुछ युवकों के नाम लोगों के बीच चर्चा में हैं। इनमें ऋतिक, रमन, निंहाल, लकी और प्रिंस सौखी मोहल्ला, आदित्य एफसीआई क्षेत्र, विक्रम और राज सिंधी बाजार, अनुज और राज खेर माता मंदिर क्षेत्र, मोनू और आशीष सिंहपुर, शशांक स्टेडियम रोड, अंकित और हर्ष मोहनराम तालाब तथा राज बस स्टैंड क्षेत्र शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बाणगंगा इलाके से डीके नाम के व्यक्ति की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं सामने आ रही हैं। हालांकि इन नामों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जबकि मुख्य सरगना के नाम के सामने की जल्द आशंका जताई गई है।

दूसरे शहरों से जुड़े होने की आशंका

स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि इस नेटवर्क के तार केवल शहडोल तक सीमित नहीं हैं। रायपुर, भिलाई, जबलपुर, भोपाल, दिल्ली और गोवा जैसे शहरों से भी इसके संपर्क होने की बात कही जा रही है। यदि इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जाए तो कई आर्थिक लेन-देन और अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकता है।

मोबाइल और ऑनलाइन रिकॉर्ड से मिलेगा सुराग

साइबर मामलों के जानकारों की माने तो इस तरह की गतिविधियों में मोबाइल फोन और डिजिटल ट्रांजेक्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंकिंग ऐप, कॉल रिकॉर्ड और ऑनलाइन भुगतान का डेटा जांच एजेंसियों को पूरे नेटवर्क तक पहुंचने में मदद कर सकता है।

हालिया घटना के बाद बढ़ी चिंता

शहर में हाल ही में घटी एक दर्दनाक घटना के बाद ऑनलाइन गेमिंग को लेकर लोगों की चिंता और बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि गेमिंग की लत और कर्ज के दबाव में एक व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ आत्मघाती कदम उठा लिया, जिसमें परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद शहर में आक्रोश और चिंता का माहौल है।

प्रशासन से कार्रवाई की दरकार

स्थानीय लोगो का कहना है कि यदि ऐसे नेटवर्क पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो कई और युवा इसके जाल में फंस सकते हैं। लोगों ने पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि संदिग्ध बैंक खातों, मोबाइल डेटा और ऑनलाइन लेन-देन की जांच कर पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

शहडोल में गैस, पेट्रोल-डीजल की पर्याप्त उपलब्धता : कलेक्टर

राष्ट्रबाण शहडोल| संवाददाता rashtrabaan.in

कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने जिले के नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि शहडोल जिले में एलपीजी, पीएनजी गैस, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है तथा उपभोक्ताओं को नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 21 गैस एजेंसियां और 70 पेट्रोल-डीजल पंप संचालित हैं, जहां से आमजन को लगातार सेवाएं मिल रही हैं। कलेक्टर ने कहा कि कुछ स्थानों पर आवश्यक वस्तुओं की कमी को लेकर अफवाहें फैलायी जा रही हैं। नागरिकों को ऐसी भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और अनावश्यक रूप से घबराने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा आपूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही लोगों से एलपीजी सिलेंडर का अनावश्यक भंडारण न करने की भी अपील की गई है। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने नागरिकों से कहा कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से प्रसारित किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना या अफवाहों पर विश्वास न करें तथा शांति और संयम बनाए रखें। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

घरेलू सिलेंडर ही बना व्यवसायियों की प्राथमिकता

गैस की कमी से आम जनता परेशान, चौपाटी में कमर्शियल सिलेंडर सिर्फ सजावट

राष्ट्रबाण शहडोल| संवाददाता rashtrabaan.in

शहर में गैस उपभोक्ताओं के लिए रोजमर्रा की परेशानी बनती जा रही है। एक ओर गैस एजेंसियों के सामने लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं वहीं नगर की चौपाटी और कई अन्य जगहों पर घरेलू सिलेंडर का उपयोग हो रहा है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर सिर्फ शोकेस के तौर पर मौजूद हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। उपभोक्ताओं ने बताया कि कभी-कभी तो सुबह जल्दी पहुंचने के बावजूद भी सिलेंडर नहीं मिल पाते। कई लोगों का कहना है कि उन्हें रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए घर से बाहर निकलकर घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिससे समय की भारी बर्बादी होती है।

घरेलू सिलेंडर का वाणिज्यिक उपयोग

नगर की चौपाटी और आसपास के कई रेस्तरां तथा होटल अब घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल कर व्यावसायिक काम कर रहे हैं। यह कदम सिलेंडर की कमी और महंगी दरों के कारण उठाया गया है। दुकानदार और व्यवसायी कहते हैं कि कमर्शियल सिलेंडर महंगे हैं और इस समय तो उपलब्ध नहीं है इसलिए घरेलू सिलेंडर का सहारा लेना मजबूरी बन गया है। वहीं कई लोगों का कहना है करें क्या जब गैस मिलेगा नहीं तो रिफलिंग करके काम चला रहें है।

कमर्शियल सिलेंडर केवल शोकेस के लिए

जानकरों की माने तो कई दुकानों और व्यवसायिक संस्थानों में कमर्शियल सिलेंडर केवल अलमारी या दीवार के पास रखे जाते हैं, जबकि कामकाज के लिए घरेलू सिलेंडर का प्रयोग किया जा रहा है। इससे न केवल सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है बल्कि नियमों का उल्लंघन भी हो रहा है।

कई महीनों से अटकी राजस्व वसूली

जानकरों की माने तो शहर के चौपाटी से जुड़ी राजस्व वसूली भी कई महीनों से अटकी हुई है। जिससे न केवल सरकारी खजाने पर असर पड़ा है बल्कि वितीय वर्ष पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा जिससे वित्तीय स्थिति भी प्रभावित हो सकती है।

भविष्य के लिए चेतावनी

जानकरों की माने तो घरेलू सिलेंडर का वाणिज्यिक उपयोग खतरनाक हो सकता है। गैस रिसाव या दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। जागरूक व्यक्तियों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि वह नियमों का पालन सुनिश्चित कर व्यावसायिक उपयोग के लिए सही सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करें। शहर में गैस किल्लत और राजस्व वसूली की अटकी हुई स्थिति ने न केवल उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ाई है बल्कि सुरक्षा और वित्तीय दृष्टि से भी गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। प्रशासनिक कदमों के बिना यह समस्या और गंभीर रूप ले सकती है।

तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत, पत्नी गंभीर

राष्ट्रबाण शहडोल| संवाददाता rashtrabaan.in

जिले के अमलाई थाना क्षेत् अंतर्गत शुक्रवार को राष्टीय राजमार्ग 43 पर तेज रफ्तार वाहन ने एक दंपति की स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी चला रहे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना बटुरा के पास अनूपपुर-शहडोल एनएच 43 पर हुई। बताया जा गया है कि अनूपपुर की ओर से आ रही एक स्कॉर्पियो वाहन ने सामने से आ रही स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी सवार सड़क पर जा गिरे और चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही अमलाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अग्रिम कार्रवाई की । पुलिस ने मृतक की पहचान सुंदरदास महरा उम्र 55 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं उनकी पत्नी ऊषा बाई महरा गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में शामिल स्कॉर्पियो वाहन को जब्त कर चालक को हिरासत में लिया गया है। मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है।

सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन लगवाएं : कलेक्टर

राष्ट्रबाण शहडोल| संवाददाता rashtrabaan.in

कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए बेटियों को एचपीवी वैक्सीन का टीका अवश्य लगवाएं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के निर्देश पर जिले में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि इस अभियान के तहत 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी तथा 15 वर्ष 3 माह तक की आयु की बेटियों को लगभग 4 हजार रुपये मूल्य का एचपीवी वैक्सीन का टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है। यह टीका गर्भाशय ग्रीवा सर्वाइकल कैंसर से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भविष्य में गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने जिले की सभी बहनों और बेटियों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर एचपीवी वैक्सीन का टीका अवश्य लगवाएं। जिले में एचपीवी टीकाकरण के लिए 9 स्वास्थ्य संस्थानों का चयन किया गया है, जिनमें मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल बुढ़ार और ब्यौहारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहपुर, गोहपारू और जयसिंहनगर तथा स्वास्थ्य केंद्र निपनिया और जैतपुर शामिल हैं। प्रशासन के द्वारा टीकाकरण का कार्य प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा चिकित्सकों की उपस्थिति में किया जा रहा है ताकि बेटियों को सुरक्षित और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

भीषण सड़क हादसे में एक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल

राष्ट्रबाण शहडोल| संवाददाता rashtrabaan.in

जिले के जयसिंहनगर थाना अंतर्गत देवरा जमुनिहा तिराहे पर शनिवार को दो बाइकों के बीच हुई सीधी भिड़ंत में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में दूसरी बाइक पर सवार दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि ग्राम नौगाई निवासी संतोष सिंह कवर उम्र 45 वर्ष अपनी बाइक से घर की ओर जा रहा था। जैसे ही वे देवरा जमुनिहा तिराहे के पास पहुंचा तो सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि संतोष सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते स्थानीय लोगों का तांता लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अग्रिम कार्रवाई की। पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतक की पहचान संतोष सिंह कंवर पुत्र धनपत सिंह कंवर निवासी नौगाई के रूप में की है और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में संपत्तियों के पंजीयन को आसान बनाने के लिए गए निर्णय

राष्ट्रबाण शहडोल| संवाददाता rashtrabaan.in

कलेक्टर डॉ. केदार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में शनिवार को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में संपत्ति पंजीयन प्रक्रियाओं को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संपत्तियों के पंजीयन के लिए निर्धारित की जाने वाली गाइडलाइन दरें तर्कसंगत, व्यावहारिक और वास्तविक बाजार मूल्यों के अनुरूप तय की जाएं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों को पंजीयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। बैठक में निर्णय लिया गया कि नागरिक अपने सुझाव एवं प्रस्ताव 16 मार्च तक जिला पंजीयक कार्यालय और संबंधित उप-पंजीयक कार्यालयों में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर नियमानुसार अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि मार्च माह के सभी सार्वजनिक अवकाशों के दौरान भी जिले के पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे। इससे संपत्ति पंजीयन संबंधी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होंगे और नागरिकों को सुविधा होगी। बैठक में जिले में संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने बाजार स्थितियों और नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुझाव साझा किए।

राष्ट्रबाण
सिवनी, रविवार 15 मार्च 2026

सिवनी राष्ट्रबाण

• बरघाट • छपारा • धनोरा • घंसौर • केवलारी • कुरई • लखनादौन • सिवनी ग्रामीण

ब्लड सेपरेशन मशीन आई लेकिन चालू ही नहीं हुई

• जिला अस्पताल सिवनी में मरीजों की बढ़ी परेशानी • विधायक जी मक्कार अफसरों की क्लास लगाओ

सिवनी जिला अस्पताल में लाखों रुपये की लागत से स्थापित ब्लड सेपरेशन (ब्लड कम्पोनेंट) मशीन और उसका लाइसेंस मिलने के बावजूद पिछले लगभग छह महीनों से मशीन बंद पड़ी है। इसका खामियाजा जिले के सिकल सेल, थैलेसीमिया और अन्य गंभीर रक्त रोगों से जूझ रहे मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और अन्य रक्त घटकों के लिए मरीजों को मजबूरन जबलपुर और नागपुर जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

राष्ट्रबाण सिवनी| संवाददाता
rashtrabaan.in

जिला अस्पताल सिवनी में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्थापित की गई ब्लड सेपरेशन (कम्पोनेंट) मशीन अभी तक चालू नहीं हो पाई है। हैरानी की बात यह है कि इस मशीन के लिए आवश्यक लाइसेंस भी लगभग छह माह पहले मिल चुका है, इसके बावजूद मशीन संचालन शुरू नहीं किया गया। इस लापरवाही के कारण जिले के गंभीर रक्त रोगों से पीड़ित मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है।

ब्लड कम्पोनेंट मशीन के माध्यम से एक यूनिट रक्त से कई आवश्यक घटक जैसे प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और पैक्ड रेड सेल अलग-अलग किए जा सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से उन मरीजों के लिए बेहद जरूरी होती है जो थैलेसीमिया, सिकल सेल, अप्लास्टिक एनीमिया या अन्य गंभीर रक्त संबंधी बीमारियों से पीड़ित होते हैं। इन मरीजों को अक्सर केवल प्लेटलेट्स या प्लाज्मा की आवश्यकता होती है, लेकिन मशीन बंद होने के कारण उन्हें पूरी यूनिट रक्त पर निर्भर रहना पड़ता है या फिर बड़े शहरों में जाना पड़ता है।

जिले में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे और वयस्क हैं जो नियमित रूप से रक्त चढ़ाने या प्लेटलेट्स पर निर्भर रहते हैं। विशेष रूप से थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को हर कुछ सप्ताह में रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में यदि जिला अस्पताल में ब्लड कम्पोनेंट की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो मरीजों को समय पर और बेहतर उपचार मिल सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में यह सुविधा केवल कागजों तक सीमित नजर आ रही है।

मशीन बंद होने का सीधा असर गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों पर पड़ रहा है। जब उन्हें प्लेटलेट्स या प्लाज्मा की आवश्यकता होती है तो मजबूरन उन्हें जबलपुर या नागपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता है। इससे मरीजों और उनके परिजनों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। कई बार समय पर उपचार न मिल पाने के कारण मरीजों की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है और कई तो मौत के मुंह में समा जाते है।

जिला अस्पताल सिवनी : मशीन और लाइसेंस है लेकिन जिम्मेदारी की इक्षा शक्ति नहीं।

विधायक बोले मामला गंभीर है इसे दिखवाता हूं

ब्लड सेपरेशन मशीन चालू नहीं होने की बात जब विधायक दिनेश राय के संज्ञान में लाई गई तो उन्होंने कहा यह मामला बेहद गंभीर है। इस विषय मैं विभागीय अधिकारी से चर्चा कर दिखवाता हूं। अगर विभाग को लाइसेंस और मशीन उपलब्ध हो चुकी है तो यह मशीन शीघ्र शुरू हो यह मैं जनता को आश्वासन दिलाता हूँ। मामला विधायक के संज्ञान में आने के बाद अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस गंभीर मुद्दे पर कितनी जल्दी कार्रवाई करता है। यदि ब्लड सेपरेशन मशीन जल्द शुरू हो जाती है तो यह जिले के हजारों मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।

दिनेश राय, विधायक : गरीबो को आस, मिले मशीन की सौगात का लाभ।

जयपाल सिंह ठाकुर, सीएचएमओ : गरीबो की परेशानी से हमें क्या वास्ता।

विनोद नवकार सिविल सर्जन : अस्पताल चलाओ भगवान भरोसे।

योगेश हरिनखेड़े, जिलाध्यक्ष थैलेसीमिया जनजागरण समिति : शुरु हुई तो गरीब मरीजों को मिलेगी राहत।

मशीन शुरू हुई तो गरीब मरीजों मिलेगी राहत

थैलेसीमिया जनजागरण समिति के जिला अध्यक्ष योगेश हरिनखेड़े ने इस मामले को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल को यह सुविधा लंबे इंतजार के बाद मिली है, लेकिन मशीन चालू न होना बेहद निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि जिले में थैलेसीमिया और अन्य रक्त रोगों से पीड़ित कई बच्चे ऐसे हैं जो नियमित रूप से रक्त और प्लेटलेट्स पर निर्भर रहते हैं। यदि ब्लड कम्पोनेंट मशीन चालू हो जाए तो इन मरीजों को काफी राहत मिल सकती है। योगेश हरिनखेड़े के अनुसार ब्लड सेपरेशन मशीन चालू होने से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा सहारा मिलेगा। मरीजों को प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और अन्य रक्त घटक स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे। इससे न केवल मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा बल्कि उन्हें दूसरे शहरों में भटकने की मजबूरी भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस मशीन को जल्द से जल्द चालू कराया जाए। उनका कहना है कि यदि मशीन जल्द शुरू नहीं हुई तो गंभीर रोगों से जूझ रहे मरीजों की परेशानी और बढ़ सकती है।

लाइसेंस मशीन है फिर भी भटक रहे मरीज

स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों का भी कहना है कि जब मशीन और लाइसेंस दोनों उपलब्ध हैं तो फिर मशीन चालू करने में देरी क्यों की जा रही है। उनका मानना है कि स्वास्थ्य विभाग को इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए तुरंत कदम उठाने चाहिए, ताकि जिले के मरीजों को जरूरी चिकित्सा सुविधाएं समय पर मिल सकें। इस संबंध में जब राष्ट्रबाण ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपाल सिंह ठाकुर से संपर्क किया तो उन्होंने ने नहीं उठाया तो सिविल सर्जन नवकार दिवाकर भी फ़ोन न उठा अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आये।

नोटिस बाट कर मलाई काटने में लगे राजस्व विभाग के अधिकारी, वसूली के लिये लगे दलाल

नैनपुर निवारी और ग्रामीण क्षेत्रों की अवैध कालोनाइजर पर नैनपुर तहसीलदार मेहरबान

निवारी में सरकारी जमीन में राजस्व विभाग की साठगांठ से अवैध कालोनाइजर ने कर लिया था। कब्जा मगर शिकायत होने पर करनी पड़ी कार्रवाई तहसीलदार और राजस्व की जमीन पर चली जेसीबी तहसीलदार अवैध कालोनाइजर पर सिर्फ नोटिस देकर कार्यवाही करना भूल गए वही जिला प्रशासन भी मौन

राष्ट्रबाण नैनपुर| संवाददाता
rashtrabaan.in

नैनपुर नगर और ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी जमीनों पटवारी ने भूमाफिया और राजस्व के अधिकारियों से मिलकर शासकीय भूमि का बंदरबाट कर दिया है। वही शिकायत होने पर भी आज तक क्या और किसके विरुद्ध कार्यवाही हुई किसी को जानकारी नहीं है। फिर जिला प्रशासन सिर छूटपुट हो रहे अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मंडला सड़क मार्ग पर पंप के सामने निवारी में खसरा नंबर 434 (मदः आम सड़क रास्ता) की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाते हुए जेसीबी चलाकर जमीन को मुक्त कराया गया।

सिवनी के अवैध कालोनाइजर ने नहर की आरक्षित भूमि भी मिला ली अवैध कालोनी में

बताया जा रहा है कि 0.84 हेक्टेयर जमीन में से 0.16 हेक्टेयर क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे चंद्रकांत गढ़ेवाल (सिवनी) द्वारा कब्जा किया गया था। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटवा दिया। वही राजस्व विभाग के पटवारियों और राजस्व निरीक्षक और भू माफिया ने मिलकर श्मशान भूमि को बेच दिया मगर कार्यवाही क्या हुई सिर्फ मलाई लेकर शांत हो गई और दिखाने के लिये सिर्फ 6प्लॉट धारियों को छोड़ दिया गया है। वही जानकारी के अनुसार नहर विभाग के अधिकारियों और तहसीलदार से साठगांठ कर नहर विभाग की भूमि भी अवैध कालोनाइजर ने प्लाट में शामिल कर ली है। जिसकी जानकारी राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग को होने के बाद कोई कार्यवाही नहीं करना सवाल खड़े करता है। कि शिकायत और नहर को क्षति पहुंचने के बाद सिंचाई विभाग मोन क्यों है।

पूर्व पटवारियों के कारनामे का साथ दे तहसीलदार नैनपुर और शिकायत पर कार्यवाही करने के बजाय दबा देते है अधिकारी

इधर नैनपुर में सरकारी जमीनों को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। राजस्व, नजूल, घास और वन विभाग की जमीनों पर लगातार निर्माण और कब्जे की शिकायतें सामने आ रही हैं। कई जगह बिना अनुमति निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल नैनपुर के सामने प्रस्तावित बस स्टैंड निर्माण कार्य पर भी रोक लग चुकी है। यह क्षेत्र साइलेंट जोन में आने के कारण निर्माण को लेकर विवाद बना हुआ है। वहीं ठेकेदार को हुए भुगतान और पहले से बने निर्माण का क्या होगा, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। वही वन विभाग की भूमि होने के बाद भी पटवारी और तहसीलदार ने वन विभाग की भूमि आवंटन किया गया है। और पट्टा आबंटन किया गया है। जिससे सवाल खड़ा होता है। बड़े झाड़ के जंगल और वन भूमि का कैसे और किस अधिकारी के द्वारा पट्टा भूमि आवंटन किया गया है। जिसकी जांच होना चाहिए मामला प्रशासनिक दफ्तरों में घूम रहा है। शिकायत के बाद पत्राचार एसडीएम कार्यालय से तहसीलदार और फिर आरआई-पटवारी स्तर तक पहुंचा, लेकिन अब तक जमीन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है।

311दुकानों का मामला हाईकोर्ट में होने के बाद राजस्व विभाग ने बाजार का पट्टा आबंटन किया

नगर में 311दुकानों पर हाईकोर्ट में मामला लंबित है। मगर राजस्व विभाग के अधिकारियों ने नियम विरुद्ध कार्यवाही करते 48लोगों को धारणा अधिकार के तहत पट्टा आबंटन कर दिया गया है। जोकि जांच का विषय है। वही नैनपुर में ऐसे कई निर्माण कार्यों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि बिना अनुमति और नियमों की अनदेखी कर निर्माण कैसे हो रहे हैं। कुल मिलाकर नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और नियमों के पालन को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर एक बात तो साफ है। नगर के जिम्मेदारो को सिर्फ मलाई से मतलब किस का नुकसान होगा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है।

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस सिवनी में भाजपा प्रचार का आरोप, विरोध करने पहुंचे एनएसयूआई छात्रों को पुलिस ने रोका

राष्ट्रबाण सिवनी| संवाददाता
rashtrabaan.in

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस सिवनी में आयोजित कार्यक्रम को लेकर छात्र राजनीति गरमा गई है। एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि कॉलेज परिसर में लगातार भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बुलाकर उनका स्वागत-सत्कार किया जा रहा है तथा छात्रों को धूप में बैठाकर भाजपा का गुणगान कराया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर एनएसयूआई के पदाधिकारियों और छात्रों ने कॉलेज परिसर में विरोध दर्ज कराया।

एनएसयूआई के अनुसार कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किए जाने के बावजूद किसी भी छात्र संगठन को आमंत्रित नहीं किया गया। चाहे वह आदिवासी छात्र संगठन हो या एनएसयूआई, सभी को कार्यक्रम से दूर रखा गया। आरोप है कि इसके विपरीत भाजपा के पन्ना प्रभारियों और जिला स्तर के पदाधिकारियों को विशेष रूप से बुलाया गया और उनका सम्मान किया गया।

एनएसयूआई जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह चंदेल के नेतृत्व में संगठन के छात्र कॉलेज पहुंचे और इस व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। धनंजय सिंह चंदेल ने आरोप लगाया कि शैक्षणिक संस्थानों को राजनीतिक मंच बनाया जा रहा है, जो छात्रों और शिक्षा व्यवस्था दोनों के लिए गलत परंपरा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को धूप में बैठाकर किसी एक राजनीतिक दल का प्रचार करना उचित नहीं है।

एनएसयूआई का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई तो सत्ता का दुरुपयोग करते हुए पुलिस के माध्यम से विरोध को दबाने की कोशिश की गई। संगठन का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने के बावजूद छात्रों को रोका गया और दबाव बनाने का प्रयास किया गया। भाजपा नेता अजय बाबा पांडेय ने एनएसयूआई जिला अध्यक्ष के साथ अभद्र व्यवहार और गुंडागर्दी दिखाते हुए धक्का मुक्की की। एनएसयूआई ने मांग की है कि कॉलेज परिसर को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा जाए और भविष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सभी छात्र संगठनों को समान रूप से आमंत्रित किया जाए।

धनंजय सिंह के साथ धक्का मुक्की करते अजय बाबा पांडेय।

एनएसयूआई जिला धनंजय सिंह, जिलाध्यक्ष एनएसयूआई : सत्ता पुलिस का रही।

अजय बाबा पांडेय, भाजपा नेता : सत्ता के अहंकार में विपक्ष को दबाने का प्रयास।

समाज से बहिस्कृत करने पर देवराज ने लगाई शासन प्रशासन से न्याय की गुहार

राष्ट्रबाण सिवनी| संवाददाता
rashtrabaan.in

लालबर्रा मुख्यालय से 03 किलो मीटर की दूरी पर स्थित ग्राम बकोड़ा के देवराज पंचेश्वर पिता जयकलाल पंचेश्वर उम्र 40 वर्ष जाति मरार ने पूर्व जनपद सदस्य एवं तत्कालीन मरार माली समाज के अध्यक्ष श्रीराम नागेश्वर तथा उनकी धर्म पत्नि वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत बकोड़ा श्रीमति पुष्पा नागेश्वर पर यह आरोप लगाया है कि दोनो पति पत्नी ने द्वेष की भावना रखते हुए साजिश के तहत उन्हें मरार समाज से बहिष्कृत (बाहर) कर दिया गया है। तथा गांव में समाज का कोई भी व्यक्ति इनसे किसी भी प्रकार का सम्बंध नहीं रखता है। अगर कोई मरार समाज का व्यक्ति देवराज या इनके परिवार से बातचीत करते हुए या देवराज के घर आते जाते देखा गया तो उसे भी दंडित कर समाज से बाहर कर दिया जायेगा।

देवराज पंचेश्वर, पीड़ित

इसी डर की वजह से ग्राम बकोड़ा मरार समाज के लोग किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में देवराज या उसके परिवार को आमंत्रण -- निमंत्रण नही देते हैं। तथा समाज का कोई भी व्यक्ति देवराज एवं उसके परिवार को काम (मजदूरी) पर भी नहीं बुलाते हैं। जिसके कारण उस पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो रहा है। जिसकी वजह से देवराज पंचेश्वर को पिछले 03 सालों से लगातार मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है।

देवराज का कहना हैं कि वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसके पास आय का कोई और दुसरा जरिया नहीं है। जब से समाज से बहिष्कृत किया गया है पत्नि और बच्चों को छोड़कर काम धंधे की तलाश में नागपुर (महाराष्ट्र) जाता हूं।

सरपंच एवं सरपंच पति पर लगाए गाली गलौच और मारपीट के आरोप... देवराज ने बताया कि आए दिन दोनों पति - पत्नी जान से मारने की धमकी तथा अश्लील गालियां देते रहते हैं। और तो और दोनों ने मिलकर दिनांक 16/11/2025 को शाम 05 बजे सांई मंदिर चौक बकोड़ा में मुझे गंदी - गंदी गालियां देकर मुझसे मारपीट करने लगे।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक संजय बघेल द्वारा श्री सिद्धिविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एमपी नगर भोपाल म.प्र से मुद्रित कराकर शिवनगर कॉलोनी सड़क मोहल्ला मरझोर जिला सिवनी से प्रकाशित।
RNI NO.: MPHIN/2015/72804 , **संपादक* संजय बघेल** पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र सिवनी होगा। E-mail: rashtrabaan@gmail.com. mob: 7000427433